उस मीटिंग में इस मसले पर बातचीत हुई थी। रोडेन्ट कंट्रोल के लिए हुकूमत कदम उठा रही है। उसके मातहत हम खाने की चीज के साथ जहर मिलाकर और ट्रेप लगा कर रोडेन्ट्स को मारते है। इसके लिए कई तरीके है। चूहों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है।

श्रीमती शीला कौल : क्या यह सच है कि चूहे एक दिन में एक आदमी का खाना खा लेते है? पेस्ट कंट्रोल की प्लान के मातहत जो काम किया जा रहा है, उसमे बहुत ढील हो जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं के बीज बोये जाते है और चूहे उनको खा लेते है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल की मेडिसन्ज बाद मे बांटी जाती हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कदम उठा रही है?

श्री शाहनवाज खां : यह सही है कि चूहे बहुत बड़ी मिकदार मे अनाज खा जाते है। कितने चूहे एक आदमी का खाना खा सकते है, यह बात इस पर भी मुनहसिर है कि कोई आदमी कितना खाना खाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारी प्रोडक्शन को बढाने के लिए पेस्ट कंट्रोल बहुत आवश्यक है। हमने जितनी भी रस्ट-प्रूफ वैरायटीज निकाली है, वे टोटल फेल्योर साबित हुई है। मैं यह जानना चाहता हू कि गवर्नमेंट एक सही रास्ट प्रूफ वैरायटी तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। हमारे देश के कई क्षेत्रों में रस्ट एपिडेमिक के रूप मे फैल रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्री शाहनवाज खां : हमारे जितने रिसर्च इंस्टाट्यूट्स हैं, खास तौर से आई० ए० आर० आई०, वे हर वक्त रस्ट-रेसिस्टेंट वैरायटीज की खोज मे मसरूफ है। माननीय सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि हमने ऐसी वैरायटीज निकाली हैं, जो रस्ट-रेसिस्टेंट है। अगर माननीय सदस्य मुनासिब समझे, तो मैं उनको पूसा ले चलूंगा और उन को कुछ वैरायटीज दिखाऊंगा।

Sugarcane Arrears

+

*188. SHRI SARJOO PANDEY:

SHRI P. M. MEHTA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Sugar Mills in different States owe huge amounts to the cane-growers;

(b) if so, the quantum of such dues in each of the sugarcane producing State, separately, and

(c) how do Government propose to help the growers to realise their dues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN). (a) and (b) A statement showing State-wise the arrears of cane price relating to 1975-76 and earlier seasons as on 15-2 1976 is placed on the Table of the Sabha Placed in Library. See No LT-10489/76.

(c) The State Governments have been advised from time to time to ensure prompt payment of cane dues by factories, take stringent measures against defaulting factories including their prosecution, make provisions in their enactments for payment of interest at 12 per cent and take steps for recovery of the arrears of sugarcane prices as arrears of land revenue. Some State Governments have already taken steps to increase the rate of interest to 15 per cent and have provided for recovery of arrears of cane price as arrears of land revenue. Legal action has also been taken in a few cases where there was delay in the payment of arrears.

श्री सुरजू पांडे : मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट रखा है, उस में भारी मात्रा में गन्ने की कीमत को बकाया दिखाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों का गन्ना खरीद लिया जाता है और उनको पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको अपनी रकम के लिए पर्ची दी जाती है। किसान अपनी 200, 300 या 400 रुपये की पर्ची को बंधक रख कर 50, 100 रुपया ले कर अपना काम चलाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसी कितनी मिलें हैं, जिन पर गन्ने की कीमत का बकाया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि पहले सालों के मुकाबले में इस साल हालत बिल्कुल बदली हुई है। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, मौजूदा साल 1975–76 के लिए 15 फरवरी, 1976 तक 8537 लाख रुपये का गन्ना खरीदा गया, जिस में से 6810 लाख रुपये का पेमेंट हो चुका है। जो पंद्रह दिन की मोहलत मिलती है, उसमें 1892 लाख रुपये का गन्ना खरीदा गया। और जो कुल बकाया है उत्तर प्रदेश का वह 17 करोड़ के करीब है। तो आप देखेंगे कि न केवल कोई एरियर्स नहीं है इस साल उत्तर प्रदेश में बल्कि एडवांस पेमेंट भी कर दिया है जिस के लिए मैं उत्तर प्रदेश को मुबारकबाद देता हूं।

श्री सरजू पांडे : दूसरा सवाल यह है कि कितनी मिलों पर आप ने ऐक्शन लिया है ?

श्री शाहनवाज खां : 17 करोड़ बकाया है, लेकिन दो हफ्ते की जो मोहलत मिलती है उसको अगर शामिल किया जाय तो 18 करोड़ बनता है। इसलिए कोई बकाया नहीं है इस साल में।

SHRI D. K. PANDA. This has been the practice for the last so many years. So, may I know whether there were suggestions to the effect that immediate action should be taken to put them behind bars when it is proved that they are in arrears, whether any such legislative provision can be made and, if not the reasons therefor?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: As I said, some State Governments have enacted legislation to take penal action against the defaulting millowners, by this year, as a result of the instructions issued by the Reserve Bank and the vigilance exercised by the State Governments and the district authorities, the position of payment of the price of cane is very satisfactory

श्री रामदेव सिंह : मंत्री महोदय ने इस साल की बात उत्तर प्रदेश की की। मैं जानना चाहता हूं कि इस सीजन के पहले सीजन्स के कितने पैसे उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों के मिलमालिकों के ऊपर बाकी है ? दूसरा आप डेफिनिट यह बताएंगे कि बकाये की वसूली के लिए किस किस फैक्ट्री का प्राजीक्यूशन उत्तर प्रदेश और बिहार में किया ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने अर्ज किया कि जो माजदा साल है इस साल में पोजीशन बहुत अच्छी है। मैं मानता हूं कि लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये पिछले साल के और उस के पहले के सालों के ड्यूज के बकाया हैं। उस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐक्शन भी लिया है। मैं जानता हूं कि एक दो मिलों के ऊपर ऐक्शन लिया जैसे मेरठ की यशवंत शुगर मिल के मालिक को जेल में भी भेजा। लेकिन जब हम ने पीनल ऐक्शन शुरू किया तो कुछ स्टे आर्डर्स मिल गए हैं कोर्ट की तरफ से इसलिए कुछ मजबूरी हमारे सामने आ गई।

श्री रामदेव सिंह : मैंने दो प्रश्न किए, एक का भी उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस से अच्छा शायद वह उत्तर नहीं दे सकते हैं।

SHRI B. V. NAIK: From the statement it is seen that during the current year with a comparatively bad performance in U. P., Bihar and even Maharashtra, they have paid about Rs. 203 crores for the whole country up to 15th February. In spite of it there are about Rs. 4 crores pending for 1974-75. How is it that the sugar factories can disperse money to the extent of Rs. 203 crores up to date and still keep arrears of Rs. 4 crores for a period of 1 to 1½ years pending? Why is it that the off-set is not given in regard to the old dues? When the sale of sugar, which is the ultimate product out of sugarcane as raw material, is absolutely on a cash and carry basis, what stands in the way of the Government seeing to it that the sale of cane by the cultivators to the factories is also done on a cash and carry basis? It might take time to implement it, but at least in principle will the hon. Minister agree that the payment should be made in cash?

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: By the very nature of the sugar industry, many problems have cropped up. If we insist on cash payment, it is not possible, because the factories may not have that much cash. I think it has been agreed upon by the representatives of the industry as well as the representatives of growers that a period of a fortnight may be allowed for making payments and from this year, that period is being adhered to and enforced successfully.

SHRI B. V. NAIK: You did not answer part (a) of my question please.

श्री नरसिंह नारायण पाँडे : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जवाब देते हुए यह कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई बकाया नहीं है इस साल का ।

यह जो केन का पेमेंट किया गया यह सोसाइटियों के खाते में किया गया और जो सोसाइटियों के ड्यूज थे उस में सोसाइटियों ने उस पेमेंट को मुजरा कर लिया और जहां तक केन के ड्यूज का ताल्लुक है पूर्वी उत्तर प्रदेश की कोई मिल नहीं है जिस के ऊपर 20–20, 30–30 और 40–40 लाख रुपये बाकी न हों। आठ दस मिलें आज भी वहां बन्द हो गई। प्रोडक्शन पर भी इस का असर पड़ता है। जो हमारा लक्ष्य था कि 50 लाख टन शुगर का प्रोडक्शन मिलेगा वह इस तरह से 45 लाख टन भी नहीं होने जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह फिगर दी है यह केन एरियर्स के ड्यूज की है या सोसाइटियों ने जो रुपया अपने खाते में जमा कर लिया उस की है ?

श्री शाहनवाज खां : शूगर प्रोडक्शन की जो बात आप ने कही है उस का इस सवाल से कोई खास ताल्लुक नहीं है क्यों कि शुगर प्रोडक्शन जो है . . . (**व्यवधान**) . . . ड्यूज की वजह से कोई मिल बन्द नहीं हुई है। जहां जहां गन्ना खत्म हो गया . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पूछा था कि जो कोई बकाया नहीं है वह क्या इसलिए नहीं है कि वह सोसाइटियों के ड्यूज में चला गया ?

श्री शाहनवाज खां : शुगर प्रोडक्शन की बात भी उन्होंने कही थी।

अध्यक्ष महोदय : उस का जवाब आप अभी मत दीजिए।

श्री शाहनवाज खां : जो पेमेंट केन डेवलपमेंट सोसाइटीज के थ्रू हुआ है, जो एक नार्मल प्रैक्टिस है कि केन डेवलपमेंट सोसाइटी जो किसान को पहले दर्जा देती है खाद की शक्ल में या और इस किस्म की,

वह अपने ड्यूज काट लेती है और यह गन्ने की कीमत की पेमेंट जो है यह केन डेवलपमेंट सोसाइटीज के थ्रू की गई है।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रश्न का जवाब तो दिला-इए, मैंने प्रोडक्शन के बारे में पूछा था . .

अध्यक्ष महोदय : वह आप बाद में इन से टेक अप कीजिए।

Convention of the Cooperative Group Housing Societies in Delhi

†SHRI D. K. PANDA:

189. SHRI JHARKHANDE RAI:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government have received the recommendations made by the convention of the Cooperative Group Housing Societies held in Delhi on the 8th February, 1976, and

(b) if so, their main demands, and decision taken, thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a): Yes, Sir.

(b). That the group housing Societies should be given land at cheaper rates, near the place of duty of its members, that normal ground rent should be charged, and the societies should be allowed to cover more area and loans should be given to the soeities for constructing houses at cheaper rates. No decision has yet been taken.

SHRI D. K. PANDA: The question is that this statement lacks proper appreciation of the seriousness of the problem, because in order to secure land, loan, etc., the Convention suggested and made recommendations for specific measures such as (1) to set up a central body; (2) to evolve some common measures of policy with regard to various societies; (3) to remove all the obstructed laws passed by different States. It has already been specifically pointed out by our Prime Minister when she made an inaugural address; and (4) to evolve a self-supporting and self-generating process. In view of these things and especially in view of the 20-point programme, how best it can be implemented? Merely taking loan at cheaper rates will not solve the problem unless proper methods are adopted and some machinery is set up. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to take action immediately in the light of recommendations made by the Convention?

SHRI H. K. L. BHAGAT: As I have submitted earlier, this Convention was held recently. They sent these recommendations and those recommendations are under examination. They have been making some of these recommendations even earlier also. One or two of them were considered by a committee which was appointed on the working of the D.D.A. The recommendations of that Committee are also being processed by a Committee consisting of representatives of different Ministries.

SHRI D. K PANDA: The hon. Minister says that the Government has yet to take a decision. I want to know by what time the decision will be taken, when all these things are going to be processed and a policy laid down.

SHRI H. K. L. BHAGAT: As I said, these recommendations have been made recently by the convention which was held about a month back. They have been received by the Government. Naturally, the Government has to examine them. But I can tell one thing that the Government is very much interested in accelerating the process of house building by cooperative societies and whatever and wherever the snags, the attempts are being made to remove those snags.